पूरन चंद

बनाम

हरियाणा राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 1818)

निर्णय 13-05-2010

(वीएस सिरपुरकर, जे; मुकुंदकम शर्मा, जे)

- दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) - धारा 302 सपिठत धारा 34

विवाहिता की जलने से मृत्यु न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा दर्ज किया गया मृत्यकालीन बयान-जब डॉक्टर ने मेडिकल प्रमाण पत्र दिया कि मृतक मृत्युपूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में थी- ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों अर्थात् मृतका के पति, देवर और चाची सास को मृत्यु कालीन कथन के आधार पर दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने चाची-ससुर को बरी कर दिया, लेकिन पति और देवर की सजा की पुष्टि की-इस आधार पर कि मरने से पहले दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में जीजा द्वारा अपील-अभिनिर्धारित किया गयाः मृत्युपूर्व कथन को एक स्वतंत्र गवाह द्वारा दर्ज किया गया था, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के रूप में काम कर रहा था, और इसके शुरू होने से पहले, मजिस्ट्रेट ने मृतक की मृत्युपूर्व कथन करने की क्षमता के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया था। मुत्युपूर्व बयान देने के लिए पीड़ित की उपयुक्तता के संबंध में डॉक्टर से पुष्टि भी ली गयी थी। मुत्युपूर्व बयान न केवल स्वैच्छिक था बल्कि विश्वनीय भी था और इसलिए, इस पर भरोसा किया जा सकता था, जैसा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किया गया था। अपीलकर्ता जीजा की सजा जारी रखी गई।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 32 मृत्युपूर्व कथन को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्तों को दोहराया गया। विवाहिता की जलने से मौत हो गई। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि मृतक पर मिट्टी का तेल छिड़का गया था और उसके बाद उसे आग लगा दी गई थी। घटना के अनुसार, मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने मृत्यु पूर्व बयान दिया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीडब्ल्यू 13 द्वारा मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया था, जब पीडब्ल्यू 14, उपस्थित चिकित्सक ने चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिया था कि मृतक मृत्युपूर्व बयान देने के लिए उपयुक्त बयान देने के लिए उपयुक्त मानसिक स्थिति में थी।

ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से उक्त मृत्यु पूर्व दिए बयान पर भरोसा करते हुए तीनों अपराधियों अर्थात मृतका के पति, जीजा और चाची को धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने चाची सास को बरी कर दिया लेकिन पति और देवर की सजा की पुष्टि की। पति ने आगे कोई अपील दायर न करने का फैसला किया।

हालांकि जीजा यानी अपीलकर्ता ने इस अदालत के समक्ष अपनी सजा को चुनौती दी और तर्क दिया कि, सबसे पहले, अपीलकर्ता का नाम मरने से पहले दिए गए बयान में नही पाया गया था और केवल जेठ (पति के बढ़े भाई) का संदर्भ था, कि मृतका के पति का एक और भाई था, और यह निश्चित नहीं था कि मृतका ने अपीलकर्ता को संदर्भित किया था या नहीं। आगे तर्क दिया कि मृतक 90 प्रतिशत जल चुकी थी और इसलिए यह संभव नहीं था कि वह मृत्युपूर्व बयान देते समय होश में होगी, जब्त किए गए कपडो पर मिट्टी के तेल के अवशेष नहीं पाए गए और यह भी कि पीडब्ल्यू-5, पीडब्ल्यू 10 और पीडब्ल्यू 8 के साक्ष्य, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा की गई थी, पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्यों मद्देनजर भी विश्वसनीय नहीं थे, जिन्होंने कहा था कि मृतक द्वारा मौखिक मृत्यु पूर्व बयान नहीं दिया गया था। अपील को खारीज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आम तौर पर, हालांकि मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा एक अत्यन्त कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, एक जली हुई महिला के लिए अपने चचेरे भाई, पीडब्ल्यू 5, पिता पीडल्यू

1 और पीडब्ल्यू 8 जैसे अपने निकट संबंधियों पर विश्वास करना अप्राकृतिक नहीं होगा। मृतका अपनी मृत्य के कारण के बारे में स्वयं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक होगी। यदि अभियोजन पक्ष केवल मौखिक मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा करता, तो चीजें अलग हो सकती थी। हालॉकि, मृत्युकालीन कथन, उदाहरण पी.एफ./3, जो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा दर्ज किए गए है। {पैरा 8} {31 एफएच 32-एबी}

मृत्यु पूर्व बयान एक स्वतंत्र गवाह द्वारा दर्ज किया गया है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के रूप में काम कर रहा था और इसके शुरू होने से पहले, मजिस्ट्रेट ने मृतक की मृत्युपूर्व बयान के अंत में यह भी पुष्टि की थी कि वह अपना बयान देते समय होश में थी और मानसिक स्थिति में फिट थी। उनसे बिना किसी सफलता के विस्तृत विवरण में जिरह की गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बयान देते समय मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक कमजोर तर्क उठाया गया कि आरोपी एक दर्जी था, फिर भी मृतक द्वारा उसका व्यवसाय एफ को शिक्षक बताया गया था। इसकी एक सरल व्याख्या है कि आमतौर पर दर्जी को टेलर मास्टर कहा जाता है। हो सकता है कि यही अभिव्यक्ति मृतक ने भी प्रयोग की हो। इस मामले के रिकार्ड में अन्यत्र भी ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। भ्रम भी शायद "मास्टर" शब्द के प्रयोग के कारण उत्पन्न हुआ होगा। मुत्यृ पूर्व बयान के अंत में भी पीडब्ल्यू द्वारा एक और समर्थन किया गया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि सबसे पहले गवाह पूरे समय सचेत थी। जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था और दूसरा उस समय उसका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था, जिस पर बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट ने भी प्रतिहस्ताक्षर किए थे। मृत्यु पूर्व दिया गया बयान न केवल स्वैच्छिक था बल्कि विश्वसनीय भी था और इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता था जैसा कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट द्वारा किया गया था। {पैरा 9, 10} {32 बीई 33-बी-ई}

2.2 निचली अदालतों को मृत्यु पूर्व दिए गए बयान से निपटते समय बेहद सावधान रहना पड़ता है क्योंकि बयान देने वाला जिरह के लिए उपल्बध नहीं होता है जिससे आरोपी व्यक्ति के लिए बड़ी कठिनाई पैदा

होती है। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर सिर्फ इसलिए भरोसा करने का यांत्रिक दृष्टिकोण बेहद खतरनाक है। न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कि क्या मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वैच्छिक है, विश्वसनीय है, मन की सचेत अवस्था में दिया गया है और मौजूद रिश्तेदारों या जांच एजेंसी से प्रभावित हुए बिना दिया गया है, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की ईमानदारी से जॉच करनी होती है। जॉच की सफलता में दिलचस्पी है या जो मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करते समय लापरवाही बरत सकता है। कई बार एक युवा लड़की या पत्नी जो मृत्यु पूर्व बयान देती है , वह इस धारणा के तहत हो सकती है कि वह केवल अपने पति के साथ शांतिपूर्ण, खुशहाल औरा आनन्दमय वैवाहिक जीवन जी सकेगी और इसलिए असुविधाजनक ससुराल या अन्य रिश्तेदार को फंसाने की प्रवृत्ति रखती है। {पैरा 11}{33-एफएच 34 एबी}

2.3 कई बार रिश्तेदार जॉच एजेंसी को प्रभावित करते है और मृत्यु पूर्व बयान दिलवाते हैं। जॉच एजेंसियो द्वारा दर्ज किए गए मृत्युपूर्व बयानों की बहुत ईमानदारी से जॉच की जानी चाहिए और कोर्ट को उस समय सभी संबंधित परिस्थतियों में जीवित रहना चाहिए, जब मृत्युपूर्व बयान अस्तित्व में आता है। जब एक से अधिक मृत्युकालीन बयान होते है, तो उन मृत्युपूर्व बयानों में आंतरिक विरोधाभास अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मृत्युकालीन कथन जो अकेले अभियोजन का समर्थन करती है, को स्वीकार किया जा सकता है जबकि अन्य निर्दोष मृत्युकालीन घोषणा को अस्वीकार करना होगा। ऐसी प्रवृत्ति बेहद खतरनाक होगी। हांलाकि निचली अदालते मृत्युपूर्व दिए गए बयानों पर कार्यवाही करने और उन्हें सजा का आधार बनाने के लिए पूरी तरह से हकदार है, जहॉ मृत्यु से पहले दिए गए बयान उपरोक्त सभी परीक्षणों को पास कर लेते है। {पैरा 11} {34-एडी}

2.4 फिर मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज करना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ तथ्यात्मक त्रृटियां हुई है। न्यायालय को सभी संबंधित परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा और स्वतंत्र निष्कर्ष पर आना होगा कि क्या मृत्यु पूर्व बयान ठीक से दर्ज किया गया

था और क्या यह स्वैच्छिक और सच्चा था। एक बार जब न्यायालय आश्वस्त हो जाता है कि अंतिम बयान इस प्रकार दर्ज किया गया है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है और उसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। न्यायालयों को यह ध्यान मे रखना चाहिए कि प्रत्येक आपराधिक मुकदमा एक व्यक्तिगत पहलू है। यह कुछ या अन्य मामलों में अन्य परीक्षणों से भिन्न हो सकता है और इसलिए मृत्युपूर्व घोषणा के कानून के लिए एक यांत्रिक दृष्टिकोण से बचना होगा। {पैरा 12}{34-ईजी}

2.5 जो घोषणा स्वैच्छिक और सत्य पाई गई है और जो किसी भी संदेह से मुक्त है, वह आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार हो सकती है। वर्तमान मामले में मृत्यु पूर्व दिया गया बयान उपर उल्लेखित सभी परीक्षणों में खरा उतरता है। {पैरा 13} {34-एच,35-एबी,36 सी}

एफ शाम शंकर कांकरिया बनाम महाराष्ट्र राज्य **2006) 13 एससीसी 165,** पानीबेन बनाम गुजरात राज्य **(1992) 2 एससीसी 474,** मुन्नू राजा बनाम मध्यप्रदेश **(1996) 3 एससीसी 104,** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव **(1985) 1 एससीसी 552,** रमावती देवी बनाम बिहार राज्य **(1983) 1 एससीसी 211,** के रामचन्द्र रेड्डी बनाम जी लोक अभियोजक **(1976) 3 एससीसी 618,** रशीद बेग बनाम मध्यप्रदेश राज्य **(1974) 4 एससीसी 264,** काके सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य **{(1981) समर्थन। एससीसी 25,** राम मनोरथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1981) 2 एससीसी 654,** महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू **(1980) पूरक एससीसी 455,** सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य एच सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 26 **{2010} 7 एससीआर ए (1980)** सपोर्ट **एससीसी 769,** नन्हौ राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(1988) सप्लि. एससीसी 700,** गंगोत्री सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1993) सप्प (1) एससीसी 327,** गोवर्धन रावजी प्यारे बनाम बी महाराष्ट्र राज्य **(1993) सप्प (4) एससीसी 316,** मीसाला रामकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **(1994) 4 एससीसी 182** और राजस्थान राज्य बनाम किशोर **(1996) 8 एससीसी 217** पर भरोसा किया।

3.जहॉं तक इस तर्क का संबंध है कि मृतका के आधे जले हुए कपड़ो पर मिट्टी के तेल का कोई निशान नहीं था और इसलिए, उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की पूरी कहानी पर विश्वास नहीं किया जानपा चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि इन कपड़ो की जब्ती पीडब्ल्यू-8 द्वारा साबित किया गया था। उन्होंने एक खाली डिब्बे की जब्ती के बारे में बात की, जिसमें मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, 4 या 5 जली हुई माचिस की तीलियॉं के साथ एक माचिस की डिब्बी, एक रजाई बना हुआ बिस्तर (शायद गद्दा) की गंध आ रही थी। उसमें से मिट्टी का तेल जो अधजला था और मिट्टी का कुछ नमूना। उनके मुताबिक, इन्हें पार्सल में अलग-अलग पैक करके सील कर दिया गया था। इस पृष्टभूमि में जब रिकवरी मेमो देखा गया तो उसमें एक खाली टीन का डिब्बा, माचिस की डिब्बी, दो जली हुई माचिस की तीलियॉं, प्लास्टिक की डिब्बी में डाली गई मिट्टी, हल्के रंग के मृतक के कपड़े, चादर (बिछौना) का जिक्र है। ताजा जलने के निशान। हालॉंकि, गवाह ने अपने परीक्षण-प्रमुख में कपड़ेे के पार्सल (प्रदर्शनी 4) का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें एफ के साथ कपड़े के कुछ आंशिक रूप से जले हुए टुकड़े हैं। एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदर्शनी 5 में केरोसिन के अवशेष पाए गए, जो एक प्लास्टिक बैग था जिसमें आंशिक रूप से जला हुआ रंगीन चेक कपास गद्दा था। यह स्पष्ट रूप से सुझाव देगता है कि प्रदर्शन 1, 2, 3, जी 4 या 6 पर कोई केरोसिन अवशेष नहीं पाया जा सकता है। इससे यह आग्रह किया गया कि विशेष रूप से, पार्सल संख्या 1, 3 और 4 केरोसिन अवशेष ले जाने के लिए बाध्य थे यदि अभियोजन पक्ष कहानी विश्वसनीय थी। हालॉंकि, यह देखा जाना चाहिए कि गद्दे में केरोसिन के अवशेष थे। जबकि घटना 15.12.2019 को हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि पार्सल एच केवल 29.12.2017 को भेजा गया था, यानी घटना के 14 दिनों के बाद, जो एफएसएल प्रयोगशाला में 31.12.1997 को पहुॅंचा था। एफएसएल रिपोर्ट की तारीख 05.06.1998 है। इस प्रकार लेखों के खोने की संभावना है। समय के लंबे अंतराल के कारण मिट्टी के तेल के अवशेष, फिर भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गद्द, जो निस्संदेह एक मोटी सामग्री है, में मिट्टी के तेल के अवशेष थे।

आमतौर पार गद्दठे पर केरोसिन वाले प्लास्टिक कंटेनर में भी केरोसिन का कोई अंश नहीं पाया गया। इसलिए इस परिस्थिति से आरोपी को मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस गद्दे पर मृतक सो रहा था ठस पर केरोसनि के कुछ अंश पाए गए है। भले ही इस परिस्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्पष्ट रूप से विश्धसनीय और बेदाग पाया गया है। इससे आरोपी के खिलाफ मामला सुलझ जाएगा। {पैरा 14){36 एफडी-एच, 37 एई }

4. समग्र परिस्थतियों पर ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई सराहना और दोषिसिद्व का ठनका निष्कर्ष सही है। { पैरा 15){37-ईएफ}

केस कानून संदर्भः-

(2006) 13 सेकंड 165	भरोसा किया	पैरा 13
(1992) 2 सेकंड 474	भरोसा किया	पैरा 13
(1976) 3 सेकंड 104	भरोसा किया	पैरा 13
(1985) 1 सेकंड 552	भरोसा किया	पैरा 13
(1983) 1 सेकंड 211	भरोसा किया	पैरा 13
(1976) 3 सेकंड 618	भरोसा किया	पैरा 13
(1974) 4 सेकंड 264	भरोसा किया	पैरा 13
(1981) सप्लीमेंट सेकंड 25	भरोसा किया	पैरा 13
(1981) 2 सेकंड 654	भरोसा किया	पैरा 13
(1980) सप्लीमेंट सेकंड 455	भरोसा किया	पैरा 13
(1980) सप्लीमेंट सेकंड 769	भरोसा किया	पैरा 13
(1988) सप्लीमेंट सेकंड 152	भरोसा किया	पैरा 13

(1989) 3 सेकंड 390 भरोसा किया पैरा 13

(1982) 1 सेकंड 700 भरोसा किया पैरा 13

(1993) सप्लीमेंट(1)सेकंड 327 भरोसा किया पैरा 13

(1993) सप्लीमेंट (4) सेकंड 316 भरोसा किया पैरा 13

(1994) 4 सेकंड 182 भरोसा किया पैरा 13

(1996) 8 सेकंड 217 भरोसा किया पैरा 13

चंडीगढ़ में पंजाब ओर हरियाणा के उच्च न्यायालय के 1999 की आपराधिक अपील संख्या 565 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.03.2008 से

अपीलकर्ता के लिए ई सिबो शंकर मिश्रा।

अप्रार्थी की ओर से राव रणजीत (कमल मोहन गुप्ता के लिए)

न्यायालय का निर्णय **वी.एस.सिरपुरकर जे.** 1 द्वारा सुनाया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 34 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि/ और सजा की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का फैसला इस अपील में चुनौती में है। मूल रूप से, तीन आरोपी व्यक्ति थे, गुरदयाल (अभियुक्त नंबर 1), पूरन चंद (अभियुक्त नंबर 2), वर्तमान अपीलकर्ता और राजो देवी (आरोपी नंबर 3)। हालाँकि, आरोपी नंबर 3, राजो देवी को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था और आरोपी नंबर 1, गुरदयाल ने अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना है। केवल पूरन चंद (अभियुक्त नंबर 2) ही हमारे समक्ष अपील में है।

2. गुरदयाल की शादी 08.12.1997 को संतोष नाम की लड़की से हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शादी के एक सप्ताह बाद ही उसे दहेज के लिए परेशान किया गया और 15.12.1997 को तीन आरोपियों, mlds ifr गुरदयाल, पूरनचंद उसके बड़े जीजा और राजो देवी, आरोपी नंबर 1, गुरदयाल की चाची, ने उसे आग लगा दी। घटना सुबह करीब चार बजे की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 ने मिट्टी का तेल छिड़का और इस साजिश में राजो देवी (अभियुक्त नंबर 3)

भी एक पक्ष थी। यह सब घटना से बमुश्किल एक सप्ताह पहले हुई शादी में कम दहेज मिलने के कारण किया गया था। संतोष को पवन कुमार, पीडब्लू-4 द्वारा जनरल अस्पताल, सेक्टर-13, चंडीगढ़ ले जाया गया और अंततः उसी दिन शाम को उसने अंतिम सांस ली। यह पाया गया कि वह 90 प्रतिशत तक जल चुकी थी, लेकिन इससे पहले उसका मृत्युपूर्व बयान पीडब्लू-13, श्री एके बिश्नोई द्वारा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मृत्युपूर्व बयान को दर्ज करने से पहले, डॉ. सिरी निवास, पीडब्लू-14 द्वारा उसकी फिटनेस के बारे में एक राय ली गई थी। उक्त मृत्यु पूर्व घोषणा Ex.PF/3 है और मेडिकल प्रमाणपत्र Ex.PF/5 है। मुकदमे में उसके रिश्तेदारों, जांच दल, मजिस्ट्रेट और डॉक्टर सहित चौदह गवाहों से पूछताछ की गई। ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने राजो देवी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और इस तरह आरोपी नंबर 2, पूरन चंद अपनी सजा को चुनौती देते हुए हमारे सामने आए हैं।

3. बचाव इनकार का था और इसे एक दुर्घटना बताया गया था। वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा यह भी कहा गया था कि वह अपने भाई गुरदयाल से अलग रह रहा था और उसे अनावश्यक रूप से फंसाया गया था। बचाव पक्ष के तीन गवाहों से भी पूछताछ की गई।

4. बचाव पक्ष सफल नहीं हुआ और इसी तरह आरोपी नंबर 2 हमारे सामने है।

5. विद्वान वकील के तर्क का मुख्य आधार मृत्युपूर्व कथन के विरुद्ध था। दावा किया गया कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान पढ़ाया-लिखाया गया था। **विद्वान वकील ने ईमानदारी से तर्क दिया कि मृत्युपूर्व बयान में कुछ आंतरिक दोष थे जो इसकी विश्वसनीयता के विरुद्ध थे। यह बताया गया कि,सबसे पहले, वर्तमान अपीलकर्ता पूरन चंद का नाम मृत्युपूर्व बयान में नहीं पाया गया था और केवल जेठ (पति के बड़े भाई) का संदर्भ था। विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि आरोपी नंबर 1, गुरदयाल का एक और भाई था और यह निश्चित नहीं था कि मृतक ने आरोपी नंबर 2, पूरन चंद को संदर्भित किया था या नहीं। तब यह बताया गया कि**

मृतक संतोष 90 प्रतिशत जल चुकी थी और इसलिए, यह संभव नहीं था कि वह मृत्युपूर्व बयान देते समय होश में होगी। अंत में, यह बताया गया कि जब्त किए गए कपड़ों पर कोई मिट्टी के तेल के अवशेष नहीं पाए गए। आगे यह भी सुझाव दिया गया कि मोहन लाल (पीडब्लू-5), चंद किरण (पीडब्लू-10) और मैम चंद (पीडब्लू-8) पीडब्लू-4, पवन कुमार के साक्ष्य को देखते हुए, जिसने कहा था कि संतोष द्वारा ऐसा कोई मौखिक मृत्युपूर्व बयान नहीं दिया गया था, के साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं थे, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा दी गई थी।

6. हम सबसे पहले मौखिक मृत्युपूर्व बयान के संबंध में दावे की जांच करेंगे। साक्ष्यों में आया है कि संतोष के जलने के बाद उसे यमुनानगर अस्पताल पहुंचाया गया। जलने की सूचना पीडब्लू-4, पवन कुमार द्वारा सुबह ही पीडब्लू-5, मोहन लाल को दी गई, जिस पर दोनों अस्पताल पहुॅचे। मोहन लाल (पीडब्लू-5) के अनुसार, उन्हें संतोष ने मौखिक रूप से बताया था कि उसे दो आरोपियों ने जला दिया था, जबकि आरोपी नंबर 3, राजो देवी ने उसके हाथ पकड़े थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी नंबर 3, राजो देवी की भागीदारी के बारे में मोहन लाल (पीडब्लू -5) के साक्ष्य के इस हिस्से पर अविश्वास किया है। हालाँकि, आरोपी नंबर 1, गुरदयाल और आरोपी नंबर 2, पूरन चंद की भागीदारी के बारे में बाकी गवाही पर ट्रायल कोर्ट ने विश्वास किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस समय उसने मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया था, उसने पूरन चंद को केवल जेठ के रूप में संदर्भित नहीं किया था, बल्कि विशेष रूप से उसका नाम लिया था।

7. हमने पीडब्लू-5, मोहन लाल के साक्ष्यों की बारीकी से जांच की है। मोहन लाल (पीडब्लू-5) के साक्ष्य की पुष्टि माम चंद (पीडब्लू-8) ने की है, जो एक अन्य गवाह है जो घटनास्थल पर भौतिक वस्तुओं की जब्ती के समय मौजूद था, उनके अनुसार, उनमें मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में मृत्यु पूर्व दिए गए किसी बयान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अजीब बात है कि बचाव पक्ष द्वारा उसकी जिरह में यह बताया गया कि वह लगभग 3 बजे पोस्ट ग्रेजुएट

इंस्टीट्यूट पहुंचा था। उसने चाँद किरण और संतोष के बीच, एक संवाद का भी हवाला दिया था। जिसमें संतोष ने अपने पिता को बताया कि उसे उसके जीजा और उसके पति ने जला दिया है। इस गवाह ने उसके फूफा सास, जिसका अर्थ उसके ससुर की बहन है, द्वारा दी गई सक्रिय सलाह का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरदयाल और पूरन चंद उस समय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में मौजूद नहीं थे। यह बेहद अजीब है कि ऐसी भौतिक बातों को जिरह में रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए था।

8. इस पंक्ति में अंतिम गवाह संतोष के पिता चंद किरण (पीडब्लू-10) हैं, जिन्होंने संतोष द्वारा तीनों आरोपियों को शामिल करते हुए मौखिक रूप से मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के बारे में बात की थी। उन्होंने माम चंद, जो उनके बहनोई थे, के साक्ष्य का भी हवाला दिया था और दावा किया था कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि राजो देवी के कहने पर उसके पति गुरदयाल और उसके जेठ पूरन चंद ने उसे जला दिया था। इस गवाह से जिरह में कुछ भी सामने नहीं आया है। इन तीनों गवाहों के साक्ष्य एक-दूसरे के पूरक हैं और इस प्रकार, पवन कुमार (पीडब्लू-4) के साक्ष्य की तुलना में अधिक स्वीकार्य हैं। आमतौर पर, यद्यपि मौखिक मृत्यु पूर्व बयान बेहद कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, एक जली हुई महिला के लिए अपने चचेरे भाई, मोहन लाल (पीडब्लू-5), पिता चंद किरण (पीडब्लू-1) और मैम चंद (पीडब्लू-8) जैसे निकट संबंधियों पर विश्वास करना अप्राकृतिक नहीं होगा। संतोष अपनी मौत के कारण के बारे में खुद को व्यक्त करने के लिए उत्सुक होंगी। यदि अभियोजन पक्ष केवल मौखिक मृत्युपूर्व बयान पर भरोसा करता, तो चीजें अलग हो सकती थीं। हालाँकि, एक मृत्युपूर्व बयान है, उदाहरणार्थ पीएफ/3, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा दर्ज किया गया है और इस मामले में इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी।

9. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सबसे पहले बताया कि लिखित मृत्युपूर्व कथन में आरोपी नंबर 2 का उसके नाम से उल्लेख नहीं किया गया था। यहां तक कि आरोपी नंबर 3 राजो देवी को भी 'बुआ' कहा गया था। यह भी दलील दी गई कि चंदीराम नाम का एक और भाई था और इसलिए, संदेह का लाभ, आरोपी नंबर 2, पूरन चंद को

मिलना चाहिए। डॉ. सतबीर सिंह (पीडब्लू-9), जो पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर थे और जिन्होंने संतोष की जांच की थी, की गवाही में उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर सतही से लेकर गहरे जलने तक का उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सतही से लेकर गहरी जलन लगभग 90 प्रतिशत थी और वे प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। हालाँकि, डॉ. सिरी निवास (पीडब्लू-14), सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे जिन्होंने संतोष की जांच की और एक प्रमाण पत्र दिया था कि संतोष बयान देने के लिए फिट मानसिक स्थिति में थी। उन्होंने मृत्यु पूर्व बयान के अंत में यह भी पुष्टि की थी कि वह होश में थी और अपना बयान देते समय मानसिक स्थिति में फिट थी। उनसे बिना किसी सफलता के विस्तार से जिरह की गई है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बयान देते समय संतोष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

10. मृत्यु पूर्व बयान के बारे में जो बात हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह यह है कि,सवर्प्रथम, इसे एक स्वतंत्र गवाह द्वारा दर्ज किया गया है,जैसे श्री एस के बिश्नोई जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यरत थे, और दूसरी बात, इसके शुरू होने से पहले, मजिस्ट्रेट ने खुद को संतोष की मृत्यु पूर्व बयान देने की क्षमता के बारे में संतुष्ट कर लिया था। डॉ. सिरी निवास का समर्थन प्राप्त है। उक्त मृत्यु पूर्व घोषणा प्रश्न एवं उत्तर प्रपत्र में है और हमें प्रश्न संख्या 4 को छोड़कर कोई भी विचारोत्तेजक प्रश्न नहीं दिखता है, जिसका आशय यह है कि "क्या इस घटना के लिए कोई और जिम्मेदार है?" हालाँकि, यह कहा जाना चाहिए कि यह प्रश्न अधिक जानकारी प्राप्त करने के विचार से था जिसे वैध रूप से रखा जा सकता था। यह इस तथ्य से अलग है कि निचली अदालतों ने अंततः आरोपी नंबर 3, राजो देवी को संदेह का लाभ दिया। जो बात हमें प्रभावित करती है वह यह है कि मरने से पहले दिए गए बयान में संतोष ने विशेष रूप से अपनी सास और ससुर को यह कहकर दोषमुक्त कर दिया कि उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। एक कमजोर तर्क दिया गया कि आरोपी एक दर्जी था, फिर भी, संतोष द्वारा उसका पेशा शिक्षक बताया गया था। इसकी एक सरल व्याख्या है कि आमतौर पर दर्जी को टेलर मास्टर कहा जाता है। हो सकता है कि यही अभिव्यक्ति संतोष ने भी इस्तेमाल की हो। इस मामले के रिकॉर्ड में अन्यत्र भी ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। यह भ्रम संभवतः "मास्टर" शब्द के प्रयोग के कारण उत्पन्न हुआ होगा। यहां तक कि मृत्यु पूर्व कथन के अंत में, डॉ. सिरी निवास द्वारा एक और समर्थन किया गया था जिसमें प्रमाणित किया गया था कि, सबसे पहले, गवाह पूरे समय सचेत था जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था और, दूसरे, उसका कोई भी रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं था। जिस पर बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट ने भी प्रतिहस्ताक्षर किए थे। बचाव पक्ष के वकील के कहने पर, हमने स्वयं मूल मृत्युकालीन बयान और उस पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट भी देखी है। हमारी राय में, मृत्यु पूर्व दिया गया बयान न केवल स्वैच्छिक था बल्कि वीश्वनीय भी था

और इसलिए, इस पर भरोसा किया जा सकता था जैसा कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया था।

11. निचली अदालतों को मृत्यु पूर्व दिए गए कथन से निपटते समय बेहद सावधान रहना पड़ता है क्योंकि उसे बनाने वाला जिरह के लिए उपलब्ध नहीं होता है जिससे आरोपी के लिए बड़ी कठिनाई पैदा होती है। मृत्यु पूर्व दिए गए कथन पर सिर्फ इसलिए भरोसा करने का यांत्रिक दृष्टिकोण बेहद खतरनाक है। न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कि क्या मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वैच्छिक है, वीश्वनीय है, सचेत अवस्था में दिया गया है और मौजूद रिश्तेदारों या जांच एजेंसी, जो इसमें रुचि रखता है, से प्रभावित हुए बिना दिया गया है या नहीं, मृत्यु से पहले दिए गए बयान की ईमानदारी से सूक्ष्मदर्शी जांच करनी होती है। जांच की सफलता या मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करते समय लापरवाही हो सकती है। कई बार, एक युवा लड़की या पत्नी जो मृत्यु पूर्व बयान देती है, वह इस धारणा के तहत हो सकती है कि वह केवल अपने पति के साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, खुशहाल और आनंदमय वैवाहिक जीवन जी सकेगी और इसलिए, ससुराल वालो या अन्य रिश्तेदारों को फॅसाने की प्रवृत्ति रखती है। कई बार रिश्तेदारो को फंसाने की प्रवृत्ति रखती है कइ बार जांच एजेंसी को प्रभावित करते हैं और मृत्यु पूर्व बयान दिलवाते हैं। जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मृत्युपूर्व बयानों की बहुत ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए और जब मृत्युपूर्व बयान अस्तित्व में आए तो अदालत को सभी संबंधित परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। जब एक से अधिक मृत्युकालीन बयान होते हैं, तो उन मृत्युपूर्व कथनों में आंतरिक विरोधाभास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल अभियोजन का समर्थन करने वाला मृत्युपूर्व कथन ही स्वीकार किया जा सके जबकि अन्य हानिरहित मृत्युपूर्व कथनों को अस्वीकार कर दिया जाए। ऐसी प्रवृत्ति बेहद खतरनाक होगी. हालाँकि, निचली अदालतें मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों पर कार्रवाई करने और उन्हें सजा का आधार बनाने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं, जहां मृत्यु से पहले दिए गए बयान उपरोक्त सभी परीक्षणों को पास कर लेते हैं।

12. पुनः मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज करना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां हुई हैं। न्यायालय को सभी संबंधित परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा और स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि क्या मृत्यु पूर्व बयान ठीक से दर्ज किया गया था और क्या यह स्वैच्छिक और विश्वसनीय था। एक बार जब अदालत आश्वस्त हो जाए कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है और उसे सजा का आधार बनाया जा सकता है। न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक आपराधिक मुकदमा एक व्यक्तिगत पहलू है। यह कुछ या अन्य मामलों में अन्य परीक्षणों से भिन्न हो सकता है और इसलिए, मृत्युपूर्व कथन के कानून के लिए एक यांत्रिक दृष्टिकोण से बचना होगा। हमने इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मृत्युपूर्व बयान का परीक्षण किया है और हम संतुष्ट हैं कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय भी इस मृत्युपूर्व कथन की स्वीकार्यता के संबंध में खुद को पूरी तरह से संतुष्ट कर चुके हैं।

13. कानून अब भली-भाँति से स्थापित हो चुका है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान जो स्वैच्छिक और सच्चा पाया गया है और जो किसी भी संदेह से मुक्त है, आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार हो सकता है। शाम शंकर कांकरिया बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 13 एससीसी 165 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों का जायजा लिया है जहां मृत्युपूर्व घोषणा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं:

i)श्रीमती पाणिबेन बनाम. गुजरात राज्य,;(19 ९२) २ एससीसी ४७४;

ii)मुन्नू राजा एवं अन्य बनाम. मध्य प्रदेश राज्य,;(19 ७६) ३ एससीसी १०४;

iii)उत्तर प्रदेश राज्य बनाम. राम सागर यादव ,;(198 ५)१९८५;

iv)रमावती देवी बनाम. बिहार राज्य,(198 ३) १ एससीसी ६१८;

v)के.रामचंद्र रेड्डी बनाम. लोक अभियोजक, (19 ७६) ३ एससीसी ६१८;

vi)रशीद बेग बनाम। मध्य प्रदेश राज्य,;(19 ७४) ४ एससीसी २६४;

vii) काके सिंह बनाम एमपी राज्य (1981) सप्लिमेंट एससीसी 25;

viii)राम मनोरथ बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य,; (198१) २ एससीसी ६५४;

ix) महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू (1980) पूरक एससीसी 455;

x) सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य (1980) पूरक एससीसी 769;

xi) नन्हाऊ राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1988) सप्लिमेंट एससीसी 152;

xii) यूपी राज्य बनाम मदन मोहन ,; (1989) ३ एससीसी ३९०;

xiii)मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम. महाराष्ट्र राज्य,(1982) १ एससीसी ७००

1. उपरोक्त फैसले के पैरा 12 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान परीक्षण न किए गए सबूतों का एकमात्र टुकड़ा है और किसी भी अन्य सबूत की तरह, अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि इसमें जो कहा गया है वह निर्विवाद सत्य है और उस पर कार्रवाई करना बिल्कुल सुरक्षित है। इस न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि यदि सावधानीपूर्वक जांच के बाद अदालत संतुष्ट है कि यह सच है और मृतक को गलत बयान देने के लिए प्रेरित करने के किसी भी प्रयास से मुक्त है और यदि यह सुसंगत है, तो इसे बनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। दोषसिद्धि का आधार, भले ही कोई पुष्टि न हो। इस संबंध में, इस न्यायालय ने गंगोत्री सिंह बनाम यूपी राज्य (1993) सप्लिमेंट (1) एससीसी 327; के रिपोर्ट किए गए मामलों का उल्लेख किया है; गोवर्धन रावजी घ्यारे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1993) सप्प (4) एससीसी 316; मीसाला रामकृष्ण बनाम. एपी राज्य,; और राजस्थान राज्य बनाम. किशोर,. हम निर्धारित कानून के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हैं और यह जोड़ना जल्दबाजी होगी कि वर्तमान मामले में संतोष का मृत्यु पूर्व बयान हमारे द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षणों को पास करता है।

14. अंत में बचाव पक्ष के वकील द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि संतोष के आधे जले हुए कपड़ों पर मिट्टी के तेल के कोई निशान नहीं थे और इसलिए, उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की पूरी कहानी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि इन कपड़ों की जब्ती माम चंद (पीडब्लू-8) द्वारा साबित की गई थी। उन्होंने एक खाली डिब्बे की जब्ती, मिट्टी के तेल की गंध, 4 या 5 जली हुई माचिस की तीलियों के साथ एक माचिस की डिब्बी, एक रजाई बना हुआ बिस्तर (शायद 'गद्दा') की जब्ती, उसमें से मिट्टी के तेल की गंध, जो कि सेमल अधर्जला हुआ था और कुछ मिट्टी नमूने के बारे में बताया। उनके मुताबिक, इन्हें पार्सल में अलग-अलग पैक करके सील चिट कर दिया गया था। इस पृष्ठभूमि में जब रिकवरी मेमो को देखा गया तो उसमें एक खाली टीन का डिब्बा, माचिस की डिब्बी, दो जली हुई माचिस की तीलियाँ, प्लास्टिक की डिब्बी में डाली गई मिट्टी, मृतक संतोष के हल्के नीले रंग के कपड़े, ताजा जलने के निशान के साथ बिछौना का उल्लेख है। हालाँकि, गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कपड़े के पार्सल (प्रदर्श 4) में कुछ आंशिक रूप से जले हुए कपड़ों के टुकड़ों का उल्लेख नहीं किया है। एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदर्शनी 5 में केरोसिन के अवशेष पाए गए, जो एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें आंशिक रूप से जला हुआ रंगीन चेक कपास गद्दा था। यह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि प्रदर्श 1, 2, 3, 4 या 6 पर कोई केरोसिन अवशेष नहीं पाया जा सका। इस पर, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि विशेष रूप से, पार्सल संख्या 1, 3 और 4 में केरोसिन अवशेष ले जाने के लिए बाध्य थे यदि अभियोजन की कहानी सच्ची थी। हालाँकि, यह देखा जाना चाहिए कि गद्दे में केरोसिन के अवशेष थे। जबकि यह घटना 15.12.1997 को हुई है, ऐसा लगता है कि पार्सल 29.12.1997 को भेजे गए थे, यानी घटना के लगभग 14 दिन बाद, जो 31.12.1997 को एफएसएल प्रयोगशाला में पहुंचे। एफएसएल रिपोर्ट पर दिनांक 5.6.1998 अंकित है। इस प्रकार समय के लंबे अंतराल के कारण वस्तुओं में केरोसिन अवशेष खोने की संभावना है, फिर भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गद्दे जो निस्संदेह एक मोटी सामग्री है, उसमें केरोसिन

अवशेष थे। आमतौर पर, गद्दे पर केरोसिन अवशेष होने का कोई कारण नहीं था जब तक कि उस पर केरोसिन न डाला गया हो। यह फिर से ध्यान देने वाली बात है कि केरोसिन वाले प्लास्टिक कंटेनर में भी केरोसिन का कोई अंश नहीं पाया गया। अतः यह परिस्थिति आरोपी की मदद नहीं करेगी क्योंकि जिस गद्दे पर संतोष सो रहा था, उस पर केरोसिन के कुछ निशान पाए गए हैं। भले ही हम इस परिस्थिति को नजरअंदाज कर दें, लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान हमें स्वेच्छा से सत्य और बेदाग पाया गया है। इससे आरोपी के खिलाफ मामला सुलझ जाएगा।

15. ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट द्वारा समग्र परिस्थितियों की सराहना और दोषसिद्धि का उनका निष्कर्ष सही है। अपील का कोई औचित्य नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

अपील अस्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारी सोनल शर्मा (आज.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।